

अनियमितता

नगरीय निकाय या स्वास्थ्य विभाग के अप्सरों ने कभी इन प्लांट्स की जांच करना उचित नहीं समझा

आरओ वाटर के नाम पर हो रहा गड़बड़झाला, गुणवत्ता की भी नहीं हो रही जांच

ब्योहारी। नगरीय क्षेत्रों के कई घर एवं दुकानों में जो आरओ फिल्टर पानी लोग खरीदकर पी रहे हैं वो कितना शुद्ध है ये कोई नहीं जानता। बस शुद्ध पानी के नाम पर इसे खरीदा जा रहा है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापार इतना फल-पूल चुका है कि हर माह कई लाखों रुपए का पानी बिक रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, ब्योहारी में तकरीबन 2 हजार परिवार फिल्टर के नाम पर ये पानी पी रहा है।

गंभीर बात यह कि नगरीय निकाय या स्वास्थ्य विभाग के अप्सरों ने कभी इन प्लांट्स का जांच करना उचित नहीं समझा। शहर एवं आसपास के गांवों में आरओ (रिवर्स ओस्मोसिस) के नाम पर लोगों को साधारण पानी ही पिलाया जा रहा है। जबकि दाम आरओ पानी के ही वसूले जा रहे हैं। कम गुणवत्ता होने के कारण इस पानी से लोगों में बीमारियां फैलने का डर भी बना रहता है। कमाल की बात यह है कि पानी के ये प्लांट



बिना किसी लाइसेंस के ही शहर में चल रहे हैं।

आरओ पानी बोलकर सादे पानी का चल रहा खेल

आरओ का पानी बोलकर फिल्टर पानी को सप्लाई हो रही है। जबकि आरओ का पानी मीठा होने के साथ काफी शुद्ध भी होता है। आरओ सिस्टम के तहत पानी की कड़वाहट समाप्त हो जाती है, जबकि फिल्टर का पानी साफतों होता है लेकिन इसमें कड़वाहट नहीं जाती। अधिकतर सप्लायर आरओ का पानी कहकर फिल्टर या फिर सीधा जमीन से खींचकर केन में भरकर बेच रहे हैं जिससे उसकी शुद्धता भी प्रभावित होती है।

सप्लायर आरओ पानी इसलिए भी नहीं सप्लाई करते, क्योंकि फिल्टर सिस्टम की तुलना में आरओ का पानी काफी खर्चीला होता है।

प्रदूषित या गंदे पानी से होती हैं बीमारियां

पानी का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर पानी दूषित है तो वह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। पेट से जुड़ी अधिकांश बीमारियां पानी की खराबी की वजह से ही होती हैं। पीने के पानी की स्वच्छता के मामले में यदि कोई असावधानी होती है तो कई तरह के रोग शरीर को घेरने में देर नहीं लगते। अगर पानी में स्वच्छता नहीं होगी तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अशुद्ध पानी पीने से डायरिया, पीलिया, हैजा, टाइफाइड व जापानी बुखार आदि भयंकर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। उल्टी-दस्त होना तो बहुत मामूली सी बात है।

पैसे बचाने के चक्कर में नहीं कराते जांच

पीएचई लैब में पानी की जांच कोई भी करा सकता है। जांच के लिए निर्धारित शुल्क भी तय है। आम जनता से 600 रुपए और व्यवसायिक उपयोग वालों से लगभग 1550 रुपए लिए जाते हैं। महीने में एक बार रॉ वाटर और सप्लाई वाटर की जांच कराई जाना आवश्यक होता है, लेकिन पैसे

बढ़ रही है आरओ के पानी की मांग

ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग सादापानी की जगह पीने व खाना बनाने के लिए आरओ के पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं ऐसे में कस्बे के साथ ही गांवों में भी आरओ प्लांट खुल गए हैं। वहीं जो व्यक्ति घर पर बाजार से आरओ खरीद कर लगाने में सक्षम नहीं है वह आरओ प्लांट से आरओ पानी के कैम्पर मंगाने को मजबूर है। आरओ प्लांट मालिक के लिए बड़े स्तर पर आरओ पानी की पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। पानी की पूर्ति करने के लिए सादा पानी में पूरिया व बर्फखाल कर टंका दिया जा रहा है। जो कि आमजन की सेहत से खिलवाड़ है।

दुकानदारों में है इसकी खास डिमांड

शहरी क्षेत्र में फिल्टर पानी की कैन अब घर और दुकानों में दिखने लगी है, लेकिन जो पानी सफाई हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो आरओ का ही पानी हो। पानी के कैन सप्लाई करने वाले कई कारोबारी आरओ की बजाय सीधा जमीन से निकाला गया पानी टण्डा कर उसमें थोड़ा बहुत फिल्टर पानी मिलाकर सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं बासी पानी भी लोगों को बेचा जा रहा है। चाहे उसमें बदबू ही क्यों न आ रहे। ब्योहारी में इतना कुछ हो रहा है और प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग आंच बंद कर देता है। या यूँ समझे कि, किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है।

जमीन देने का सपना दिखाकर दीपू सोनी ने महिला से की लाखों की ठगी

नवभारत, ब्योहारी। दीपू पिता मोतीलाल सोनी निवासी वार्ड क्रमांक 09 न्यू बरौंधा ने एक बेवफा महिला को जमीन देने का सपना दिखा उसे अपने विश्वास में लेकर महिला के साथ लाखों की ठगी किया गया है। जमीन न देने पर पैसा मागने में जान से मारने की धमकी दी जा रही है जिसकी शिकायत महिला ने थाना ब्योहारी में कर न्याय की गोहार लगायी है।



मोतीलाल सोनी दोनों लोग जमीन देने के नाम पर आज 10 वर्ष से पैसा ले रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक 3 लाख रूपये दे चुका हूँ इसके बाद भी वह जमीन नहीं दे रहा है।

ऑटो विक्रेता की भूमिका सदृश

इस धोखाधड़ी में कंही न कंही ऑटो विक्रेता भी सामिल है क्योंकि महिला सफुर्निशा के नाम पर जब ऑटो विक्रेता द्वारा रसीद दी गयी तो फिर वह ऑटो सफुर्निशा के नाम पर क्यों फइनेंस नहीं कराया गया कैसे दूसरे के नाम पर ऑटो फइनेंस हो गया कंही यह सोची समझी साजिस तो नहीं यदि यह सच है तो उसके लिए ऑटो विक्रेता भी दोषी है। वरहाल देखने वाली बात यह है कि ब्योहारी पुलिस इसे कितनी गंभीरता से लेती है और महिला को न्याय दिलाने हेतु क्या कार्रवाई करती है।

कहने के मुताबिक आज तक मे कुल 3 लाख रूपये दे चुकी हूँ। अब वो लोग हमें जमीन नहीं दे रहे है। पैसा मागने व थाना मे शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी दी जा रही है।

सबूत के तौर पर मौजूद है रसीद

महिला का आरोप है कि दीपू सोनी व उसके पिता मोतीलाल सोनी द्वारा जमीन के नाम पर पैसा आर. के. मोटर्स नाम पर संचालित रेलवे तिराहा के पास ऑटो की दुकान में

जमा कराया गया और अपने नाम से ऑटो लिया गया है जिसका रसीद मेरे पास है। उनके कहने के मुताबिक 3 लाख रूपये दे चुका हूँ इसके बाद भी वह जमीन नहीं दे रहा है।

ऑटो विक्रेता की भूमिका सदृश

इस धोखाधड़ी में कंही न कंही ऑटो विक्रेता भी सामिल है क्योंकि महिला सफुर्निशा के नाम पर जब ऑटो विक्रेता द्वारा रसीद दी गयी तो फिर वह ऑटो सफुर्निशा के नाम पर क्यों फइनेंस नहीं कराया गया कैसे दूसरे के नाम पर ऑटो फइनेंस हो गया कंही यह सोची समझी साजिस तो नहीं यदि यह सच है तो उसके लिए ऑटो विक्रेता भी दोषी है। वरहाल देखने वाली बात यह है कि ब्योहारी पुलिस इसे कितनी गंभीरता से लेती है और महिला को न्याय दिलाने हेतु क्या कार्रवाई करती है।

पैसा लेने के बाद भी नहीं दी जा रही जमीन

सफुर्निशा पति स्व. सफुर्दीन निवासी वार्ड क्रमांक 03 ने दिनांक 11 मार्च 2026 को थाना ब्योहारी में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है जिसकी प्रती उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि दीपू सोनी और उसके पिता



आज मनाई जाएगी संत

शिरामणि मां कर्मा की जयंती

शहडोल। संभागीय मुख्यालय शहडोल में संत शिरामणि मां कर्मा जी की 1010वीं जयंती 15 मार्च को श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य रूप से मनाई जाएगी। यह आयोजन जिला साहू समाज शहडोल के तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले में मां कर्मा जयंती की जयंती पखवाड़े के रूप में भी मनाया जाएगा। मीडिया प्रभारी अनिल साहू ने बताया कि जयंती के अवसर पर मां कर्मा मंदिर में प्रातः 11 बजे से पूजन और भजन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मां कर्मा सेवा आश्रम एवं छात्रावास, करण तेलिया के पास कर्मा चालीसा का पाठ किया जाएगा।

श्रमिक कॉलोनी में ठेके में दी गई सफाई व्यवस्था चौपट, सड़कें भी जर्जर

धनपुरी। हर साल श्रमिक कॉलोनी में सफाई व्यवस्था को लेकर लाखों रुपए का ठेका एसईसीएल सोहागपुर प्रबंधन के द्वारा दिया जाता है ताकि कॉलोनी में सफाई व्यवस्था बेहतर रहे लेकिन लाखों का ठेका देने के बाद भी श्रमिक कॉलोनीयों का हाल क्या है यह वहां पर देखकर ही पता चलता है वैसे तो कुछ श्रमिक कॉलोनी में सफाई व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही है जहां पर सफाई ठीक भी नजर आती है लेकिन जहां-जहां एरिया प्रबंधन के द्वारा सफाई का ठेका दिया गया है।

वहां पर सफाई का क्या हाल है यह तस्वीर को उन कॉलोनी में देखकर पता चलती है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो संजय नगर कॉलोनी रिजल्ट कॉलोनी राजेंद्र कॉलोनी अरजुला कॉलोनी यहां पर सफाई के नाम पर लाखों रुपए का ठेका दिया गया है लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह से परे से उतरती हुई देखी जा रही है यही कारण है कि लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं लेकिन जिम्मेदार इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लाखों का ठेका देने के बाद भी सफाई हो रही है या नहीं



इसका निरीक्षण एरिया सिविल विभाग के अधिकारी नहीं करते यही कारण है की समस्या बरकरार इन कॉलोनी में देखने को मिलती है।

सबसे पहले अगर बात संजय नगर कॉलोनी को लेकर की जाए तो यह एरिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में सबसे अधिक समस्या भी नजर आती है पूरे कॉलोनी में हर तरफ गाबर घास देखा जा सकता है नालियां पूरी तरह से जाम हैं कचरा जहां-तहां नजर आते हैं जो इस तस्वीर को बताती है कि कॉलोनी में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है समय-समय पर कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्य एरिया वेलफेयर बोर्ड के सदस्य कॉलोनी का निरीक्षण करते हैं वहां की समस्याओं को देखते हैं प्रबंधन को इससे अवगत भी



आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग तेल विपणन कंपनियों द्वारा दिए गए विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से की जा सकती है। भारत गैस के लिए बुकिंग व्हाट्सएप नंबर 1800 22 4344, मिस कॉल 7710955555, आईवीआरएस 7715012345, मोबाइल एप हैलो बीपीसीएल तथा वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। इंडियन गैस के लिए व्हाट्सएप 7588888824, मिस कॉल 8454955555, आईवीआरएस 7718955555, मोबाइल एप इंडियन ऑयल वन

और वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार एचपी गैस के लिए व्हाट्सएप 9222201122, मिस कॉल 9493602222, आईवीआरएस 8888823456, मोबाइल एप एचपी गैस तथा वेबसाइट के माध्यम से सिलेंडर बुक कराया जा सकता है। उन्हीं नागरिकों से अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिले में गैस और इंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर बुकिंग करें और केवल आवश्यक होने पर ही गैस एजेंसी जाएं।



इसका निरीक्षण एरिया सिविल विभाग के अधिकारी नहीं करते यही कारण है की समस्या बरकरार इन कॉलोनी में देखने को मिलती है।

सबसे पहले अगर बात संजय नगर कॉलोनी को लेकर की जाए तो यह एरिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में सबसे अधिक समस्या भी नजर आती है पूरे कॉलोनी में हर तरफ गाबर घास देखा जा सकता है नालियां पूरी तरह से जाम हैं कचरा जहां-तहां नजर आते हैं जो इस तस्वीर को बताती है कि कॉलोनी में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है समय-समय पर कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्य एरिया वेलफेयर बोर्ड के सदस्य कॉलोनी का निरीक्षण करते हैं वहां की समस्याओं को देखते हैं प्रबंधन को इससे अवगत भी

सफाई व्यवस्था को लेकर सबसे अधिक सवाल उठ रहे

अब रात रीजनल कॉलोनी को लेकर की जाए तो इस कॉलोनी की सफाई व्यवस्था भी इन दोनों कई सवाल उठे कर रही है कॉलोनी में गाबर घास हर तरफ नजर आ रही है नालियां पूरी तरह से जर्जर है सड़कें का हाल भी खस्ता हाल है इतना ही नहीं शाम होते ही कॉलोनी में जगह-जगह अंधेरा नजर आने लगता है जो कि यहां की समस्याओं को बढ़ा रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर सबसे अधिक सवाल उठ रहे हैं वहां पर भी सफाई का ठेका प्रबंधन के द्वारा दिया गया है ताकि कॉलोनी में नियमित सफाई व्यवस्था होती रहे लेकिन हालात कैसे हैं इसे देखा जा सकता है इस कॉलोनी में कई अधिकारियों का निवास है इसके बाद भी जब इस तरह के हालात इस कॉलोनी में है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एरिया सिविल विभाग व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को दिशा किन्तु ध्यान दे रही है। अब बात राजेंद्र एवं अरजुला कॉलोनी को लेकर की जाए तो इस कॉलोनी में भी सफाई व्यवस्था का हाल बेहतर नजर आता है यहां की कॉलोनी में बुले वेबर भी एक बड़ी समस्या बनू हुए है कॉलोनी के अंदर जो आवास बने हुए है उनके आसपास सफाई व्यवस्था का हाल देखा जा सकता है लगातार इस पर सवाल भी उठते हैं लेकिन जिम्मेदार किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे एरिया महाप्रबंधक से इस आ ध्यान देने की मांग की गई है।

चलते हैं सवाल इस बात का उठता है कि जिस सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों का ठेका दिया जाता है सफाई ही नहीं होती भुगवान किस बात का किया जा रहा है आज भी अगर इस कॉलोनी का निरीक्षण सिविल विभाग के अधिकारी करें तो यहां की व्यवस्था किस तरह से नजर आती है यह सफा तौर पर देखा जा सकता है सवाल इस बात का भी उठता है कि लगातार एरिया श्रम संगठन के पदाधिकारी के द्वारा भी इन समस्याओं से प्रबंधन को अवगत कराया जाता है तो फिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता।

जल संरक्षण में आमजन निभाएं अपनी सहभागिता: सीईओ

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह ने 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिला पंचायत सभागार में जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में जिले में 19 मार्च से 30 जून 2026 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें। बैठक में पुराने तालाबों, कुओं, बावड़ियों एवं अन्य जल स्रोतों की साफ-सफाई तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रमिक संघों की अनेक मांगों पर बनी सहमति

धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र में आंदोलनरत श्रमिक संघों की केंद्रीय आयुक्त श्रम व प्रबंधन के साथ वार्ता कर कई मांगों पर सहमति व्यक्त की गई। संयुक्त सलाहकार समिति सहायक आयुक्त श्रम व प्रबंधन विभिन श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

श्रमिक संगठनों की ओर से कर्मचारियों का स्थानांतरण, ठेका मजदूरों की उपस्थिति व सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों व अन मांगों के संदर्भ में अपनी बात रखी। प्रबंधन ने कई विषयों पर विचार करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया की इन क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता और उत्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य व्यवस्था



की जाएगी तथा कर्मचारियों को समुचित रूप से नियोजित किया जाएगा। वाचन वार्ड से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण के विषय में भी प्रबंधन ने आवश्यक किया की कर्मचारियों की कार्य अवधि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि तीन वर्ष से कम है उन्हें आवश्यकतानुसार यथा स्थान रखा जाएगा व अन्य मामलों में कर्मचारियों की सहमति व प्रशासनिक आवश्यकताओं के

अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। सोहागपुर क्षेत्र में कार्यरत ठेका कंपनियों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें ठेका कंपनियों के कार्य आदेश व सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। प्रबंधन द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया ताकि पारदर्शिता बनी रहे व ठेका मजदूरों को मिलने वाली जानकारी व अन्य मामलों द्वारा उन्हें नियमानुसार दिया जाए जिससे उनका शोषण न हो सके व ठेका

मजदूरों की उपस्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें प्रबंधन के द्वारा सभी ठेका मजदूरों की फिजिकल अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए सभी उपक्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी किए जाएंगे जिससे मजदूरों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज होगी व ठेका कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी।

ये रहे उपस्थित

बैठक के अंत में संयुक्त सलाहकार समिति के मुख्य आयुक्त श्रम व प्रबंधन के वीपी सोहार्द पूर्ण वातावरण में वार्ता संपन्न हुई। बैठक में श्रमिक संघ से एच.एम.एस. के अध्यक्ष राकेश कांत पाण्डेय, महामंत्री नीरज चतुर्वेदी, बी.एम.एस. से हारिक प्रयास मिश्रा, आंकार दुवेदी, इंटर से महेंद्र शुक्ला, कैलाश कुमार यादव, एटके से रविंद्र शुक्ला, राजेंद्र चंद्र शर्मा, जे.सी.सी. सदस्य शिवनारायण मिश्रा (एच.एम.एस.) सीटू से विनोद राय, धीरेन्द्र पाण्डेय उपस्थित थे।

सोहागपुर एरिया के विभिन्न मुद्दों को लेकर परियोजना अधिकारी से शर्मा ने की चर्चा

धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर एरिया की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी सेपटी बोर्ड के सदस्य कमलेश शर्मा निरंतर मुख्यालय के अधिकारियों से चर्चा करते हैं और इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि यहां की समस्याओं का समय रहते समाधान हो विगत दिनों भी बिलासपुर मुख्यालय से दामिनी भूमिगत खदान में सीएम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए निर्देशक तकनीकी योजना एवं परियोजना प्रयास चंद्र महापात्रा से कंपनी सेपटी बोर्ड के सदस्य कमलेश शर्मा ने चर्चा की और यहां के विभिन्न मुद्दों से उन्हें अवगत भी कराया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए कंपनी सेपटी बोर्ड के सदस्य कमलेश शर्मा ने कहा कि विगत दिनों एरिया आए मुख्यालय से तकनीकी योजना में परियोजना अधिकारी से उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जिसमें कोयला खदानों की सुरक्षा से संबंधित भी बातें थी उन्होंने कहा कि एरिया की समस्याओं को लेकर उन्होंने जो भी बात रखी उसे उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना और इस बात का भी विश्वास



दिलया की समस्याओं के समाधान को लेकर सभी प्रयास किए जाएंगे यहां के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी उन्हीं अपनी बात रखी इसके साथ-साथ एरिया के उत्पादन को लेकर भी उन्हीं चर्चा की और वर्तमान समय में प्रबंधन जिस तरह से वार्षिक लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रही है उसकी उन्हीं सराहना भी की। वहीं शर्मा ने इस बात को भी कहा कि दामिनी भूमिगत खदान में सीएम प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से यहां का कोयला उत्पादन बढ़ेगा

जिला मूल्यांकन समिति

की बैठक आयोजित

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपत्तियों के पंजीयन हेतु निर्धारित की जाने वाली गाइडलाइन दरें तर्कसंगत, व्यावहारिक तथा वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप तय की जाएं, ताकि आम नागरिकों को पंजीयन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि नागरिक कलेक्टर गाइडलाइन से संबंधित अपने सुझाव एवं प्रस्ताव 16 मार्च तक जिला पंजीयक कार्यालय तथा संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा साथ ही नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च माह में आने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी जिले के पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे संपत्ति पंजीयन संबंधी कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।

जनपद में 'सिस्टम' का इंजन फेल

- 3 महीने से वेतन को तरस रहे उपयंत्री
- विकास कार्यों पर लग सकता 'अघोषित' लॉक

गोहपारू। शासन की विकास योजनाओं को धरातलपर उतारने का दावा करने वाली जनपद पंचायत खुद 'कुप्रबंधन' का शिकार हो गई है। जिले की महत्वपूर्ण जनपद पंचायत में पिछले तीन महीनों से उपयंत्रियों को वेतन नहीं मिला है। आलम यह है कि जो अधिकारी करोड़ों के निर्माण कार्यों की

तकनीकी स्वीकृति और मूल्यांकन करते हैं, उनके खुद के घरों का चूल्हा बुझने की कगार पर है।

आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव

लगातार 90 दिनों से मान्य/वेतन न मिलने के कारण उपयंत्रियों के सामने बैंक की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और घरेलू खर्चों का संकट खड़ा हो गया है। दबी जुबान में तकनीकी अमले का कहना है कि जब हम खुद तनाव में हैं, तो फ्रील्ड पर जाकर ईमानदार से काम कैसे करें।

ब्रध्दचार को बढ़ावा देता सिस्टम

एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यदि जिम्मेदार तकनीकी अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा, तो क्या शासन उन्हें परोक्ष रूप से 'कमीशनखोरी' की ओर धकेल रहा है? वेतन के अभाव में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता होने की पूरी आशंका बनी हुई है। उपयंत्रियों के इस असंतोष का सीधा असर ग्रामीण विकास पर दिख रहा है। कई पंचायतों में पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन तकनीकी मूल्यांकन न होने से टेकेदारों का भ्रमान अटका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही अगली किस्त के लिए उपयंत्री की जियो टैमिंग का इंजाय कर रहे हैं। इमरेंस के तहत चल रहे चेकअप और सीसी रोड के कार्य गुणवत्ताहीन हो रहे हैं। की देखरेख के अभाव में गुणवत्ताहीन हो रहे हैं। सुत्रों की माने तो बजट की उपलब्धता के बावजूद फंडों को लटकाया जा रहा है। आखिर इस देरी का जिम्मेदार कौन है? जनपद के लेखा विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतान पड़ रहा है।

